GOVERNMENT OF INDIA



# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 2] दिल्ली, जनवरी 7—जनवरी 13, 2011, बृहस्पतिवार/पौष 17-पौष 23, 1932 [रा.रा.स.क्षेदि, सं. 243, 244, 246] No. 2] DELHI, JANUARY 7—JANUARY 13, 2011, THURSDAY/PAUSA 17—PAUSA 23, 1932 [N.C.T.D. No. 243, 244, 246]

### भाग---IV PART-IV

भाग-। में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

#### ऊर्जा विभाग

### आदेश

दिल्ली, 11 जनवरी, 2011

फा. सं. 11(85)/2007/कर्जा/80.—श्री वी.पी. दत्ता, महाप्रबंधक (टी) को उपराज्यपाल, दिल्ली निदेशक (संचालन), डीटीएल के पद पर सैद्धान्तिक पदोन्नित का अनुमोदन प्रदान करते हैं। श्री वी.पी. दत्ता को पदोन्नित के लाभ वेतन आदि के पिछला बकाया के बिना दिनाक 1-2-2009 से दिये जायेंगे तथा उनके निदेशक (संचालन), डीटीएल का कार्यभार संभालने की तिथि से ही वास्तविक पदोन्नित लाभ प्रदान किये जायेंगे!

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, डॉ. हरीश के. आहुजा, संयुक्त सचिव (ऊर्जा)

### DEPARTMENT OF POWER

### ORDERS

Delhi, the 11th January, 2011

No. F. 11(85)/2007/Power/80.—Lt. Governor, Delhi is pleased to approve the promotion of Sh. V.P. Dutta, General Manager (T) to the post of Director (Operations), D.T.L. Sh. V.P. Dutta would be given notional benefit of promotion w.e.f. 1-2-2009 without any arrears of pay etc. and actual benefits of promotion only from the date he assumes the charge of Director (Operations) DTL.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

DR. HARISH K. AHUJA, Jt. Secy. (P)

13

### दिल्ली, 13 जनवरी, 2011

सं. भा. 11(125)/2010/कर्जा/93, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री आर. एस. राठी, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड को इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड तथा प्रगति पॉवर निगम लिमिटेड के महानदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर उनके कार्यभार संभालने की तिथि से नियुक्त किया जाता है।

श्री आर. एस. राठी की प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्ते यथा समय तय की जायेंगी।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेशानुसार व उनके नाम पर, डॉ. हरीश के आहुजा, संयुक्त सचिव (ऊर्जा) Delhi, the 13th January, 2011

No. F. 11(125)/2010/Power/93.—Lt. Governor, Delhi is pleased to appoint Sh. R.S. Rathee, General Manager, NTPC Limited, as Managing Director of Indraprastha Power Generation Company Limited and Pragati Power Corporation Limited on deputation basis with effect from the date of his joining.

The terms and conditions of deputation of Sh. R. S. Rathee will be decided in due course.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

DR. HARISH K. AHUJA, Jt. Secy (P) सहकरिता विभाग

# (कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ) अधिसूचना

दिल्ली, 12 जनवरी, 2011

सं. फा. 47/893/स.अ./दक्षिण पश्चिम/सह./4882. — दिल्ली सहकारी सिमितियाँ अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम-3, 2004) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सदभावना सहकारी समूह आवास सिमिति (893/स.अ.) को धारा 37 (1)(छ) दिल्ली सहकारी सिमितियाँ अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम-3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा उक्त सिमित की अतिक्रमण की अविध व प्रशासक के कार्यकाल की अविध दिनांक 30-6-2011 तक बढ़ाई जाती है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. के . झॉ, अतिरिक्त सचिव (सहकारिता)

### **DEPARTMENT OF COOPERATION**

(OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES)

### **NOTIFICATION**

Delhi, the 12th January, 2011

No. F. 47/893/GH/SW/COOP/4882.—In exercise of the powers conferred by Section 127 of the Delhi

Cooperative Socities Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby exempts the Sadbhawna Cooperative Group Housing Society Ltd. (893/GH) from the provision of Section 37(1)(b) and accordingly extend the period of supercession of the Managing Committee and the term of Administrator of the said Society up to 30-06-2011.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

S.K. JHA, Addl. Secy. (Cooperation)

### आयुक्त का न्यायालय

(व्यापार एवं कर विभाग)

### अधिसुचना

दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

विषयः वर्क संविदा की प्रवृति में सम्मिलित लेन-देन के बी. ओ.टी सर्विदा पर कर उगाही तथा तद्उपरांत अपेक्षित पंजीकरण।

सं. 281/सीडीबीएटी/2010/42,—श्री के.के. दाहिया, अपर आयुक्त (विशेष जोन) व्यापार एवं कर विभाग ने डी वी ए टी अधिनियम, 2004 की धारा 85 के अन्तर्गत याचिका दायर की, जिसमें निम्न दो बिन्दुओं पर डी वी ए टी अधिनियम, 2004 की, धारा 85 के अंतर्गत स्पष्टीकरण/रूलिंग की मांग की है:-

- (क) क्या बी ओ टी संविदा, वर्कस संविदा की प्रवृति में लेन-देन है जैसा कि डी वी ए टी अधिनियम, 2004 की धारा 2 (जेड सी) एवं (जेड ओ) में परिभाषित है ?
- (ख) यदि प्रश्न का उत्तर सकारात्मक हैं, तो क्या बी ओ टी सर्विदा को डी वी ए टी अधिनियम, 2004 की धारा 18 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने का दायित्व हैं ?

आयुक्त (वैट), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीनस्थ तथा व्यक्तियों/डीलरों जो इस प्रकार का लेन-देन करते हैं दोनों में वर्कस स्विंदा की प्रवृति में बी ओ टी स्विंदा में कर योग्य तथा पंजीकरण के संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति को अधिसृचित करने के उद्देश्य से उक्त याचिका दायर की गयी है।

- 2. बी ओ टी सिंविदा तथा इसके तकनीकी पहलुओं की कार्यवाही की प्रवृति की व्याख्या के दौरान आवेदक ने दिनांक 27-10-2010 के आवेदन में उल्लेख किया है कि बड़ी संख्या में बी ओ टी सिंविदा (बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर) कार्यरत हैं। चाहे सिंविदाएं डी एम आर सी, एयरपोर्ट, रोड या पावर इत्यादि के सबंध हैं—दिल्ली में इन परियोजनाओं के निष्पादन में सम्मिलित सामग्री पर वैट लागू है।
- 3. वैचारिक रूप से बी ओ टी सिंविदा पहले मालिक/संगठन की आवश्यकता के अनुसार मालिक/संगठन द्वारा निर्णय किए गए स्थल पर बी ओ टी सम्पित का निर्माण करेगा। ऐसे सिंविदा में पथकर ऐसा राजस्व है जोिक बी ओ टी ठेकेदार और मालिक/संगठन द्वारा हस्ताक्षरित सिंविदा की निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप बी ओ टी सम्पित के भविष्य के उपयोगकर्ता से प्राप्त करता है।

- 4. यह स्वीकार्य तथ्य है कि बी ओ टी संविदाएं विचारार्थ कई उप ठेकेदारों को बैक टू बैक आधार पर आंशिक या पूर्णत: स्थानांतरित होते हैं।
- 5. बी ओ टी मामलों में विस्तृत कार्रवाई के दावा के विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि बी ओ टी ठेकेदार सामग्री को आयात/स्थानीय खरीद करते हैं और उसे उप ठेकेदार को या प्रयोग के लिए प्रभार मुक्त आधार पर (एफ ओ सी) विभिन्न ठेकेदारों को परियोजना में स्थानांतरित करते हैं। इन लेन-देन के अंदर दिल्ली वैट अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत बड़ा राजस्व उलझा है।
- 6. विशेष जोन के एक मामले में एक बी ओ टी ठेकेदार खरीद को दर्शांकर इनपुट पर क्रेडिट/टी डी एस सर्टीफिकेट लाभ का दावा कर रहा है परंतु रिटर्न में टैक्सेबल टर्नओवर नहीं दर्शा रहा है। अवलोकन या रिटर्न से यह पता चलता है कि डीलर प्रत्येक माह में कैरी फार्वर्ड दिखा रहा है। इसी प्रकार संभावना है कि अन्य डीलर भी इस आधार पर टैक्स अदा करने से बचेंगे कि यह उनका दायित्व नहीं है क्योंकि उन्होंने संविदाकर से कोई पेमेंट प्राप्त नहीं की है।
- 7. उपरोक्त आवेदन में उठाए गए प्रश्न के संबंध में मांगा गया निर्णय यह है कि बी ओ टी संविदाएं वर्कस संविदा की प्रवृति में ट्रांजेक्शन है या नहीं और यदि हां तो क्या बी ओ टी ठेकेदारों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है ? इस संबंध में, "बिक्री" शब्द की परिभाषा को संबद्ध करना अनिवार्य है। जैसाकि डी वी ए टी अधिनियम, 2004 की धारा (2) की उप-धारा (1) के खण्ड (जेड सी) में चित्रित है जिसे निम्न प्रकार पढ़ा जाए :-

व्याकरण भिन्नता तथा सजातीय अभिव्यक्ति से "बिक्री" का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को गुड्स में प्रोपर्टी का स्थानांतरण चाहे वो नगद हो या अस्थिगत भुगतान या अन्य बहुमूल्य प्रतिफल के लिए (जिसमें अनुदान या एक सरकारी एजेंसी या विभाग द्वारा संसाहायिकी भुगतान, सिम्मिलत नहीं है चाहे वो केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार को है) और सिम्मिलित है-

v गुड्स में प्रापर्टी का स्थानांतरण (चाहे वो गुड्स में हो या अन्य किसी रूप में) वर्क्स संविदा के निष्पादन में सम्मिलित;

vi vii

VШ

8 यहाँ पर धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (जेड ओ) में उल्लिखित अभिव्यक्ति "कार्य सर्विदा" का उल्लेख करना भी संगत है जिसमें दिया गया है कि कार्य सर्विदा में किसी कार्य को नकद राशि या बाद में की जाने वाले भुगतान या मूल्यगत पारिश्रमिक के लिए करने हेतु कोई समझौता करना, भवन निर्माण, विनिर्माण, प्रक्रिया, सजावट, खडा करना, स्थापना, फिटिंग, सुधार या किसी चल या अचल सम्पत्ति को चालू करना शामिल है।

9 धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (m) में दी गई "सामान" अभिव्यक्ति की परिभाषा भी समान रूप से संगत है जिसे लिखा गया है कि-

'सामान का अर्थ' हैं सभी प्रकार की चल सम्पति (जिसमें समाचार पत्र, कार्ययोग्य दावे, स्टॉक, शेयर तथा प्रतिभूतियों को छोड़कर) तथा इसमें शामिल हैं-

- (i) पशु, समस्त सामग्री, आवश्यक वस्तुएं, घास या पृथ्वी से जुड़ी या उसका एक भाग वस्तुएं जिसकी बिक्री या बिक्री संविदा के अंतर्गत प्रदान करने पर सहमति हुई थी, तथा
- (ii) सामान में सम्पित्त (चाहे सामान या किसी अन्य रूप में हो) में किसी कार्य सींवेदा का निष्पादन, पट्टा या किराया-खरीद या सजावट में प्रयोग किया जाने वाला सामान, अचल संपित्त में सुधार या मरम्मत शामिल हैं;

10 धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (जे) में यथोल्लिखित 'व्यापारी' अभिव्यक्ति का उल्लेख भी संगत है जिसमें दिया है कि:-

"व्यापारी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यापार के उद्देश्य के लिए या अपनी सॉलिप्तता के कारण या उसके संबंध में या प्रासंगिक या उसके दौरान दिल्ली में सामान को खरीदता या बेचता है चाहे यह नकद राशि के लिए या भावी भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक के लिए या अन्यथा किसी मूल्यगत प्रतिफल के लिए हो तथा इसमें शामिल है:—"

(i) आढ्तिया, कमीशन एजेंट, दलाल, प्रत्यायक एजेंट या कोई अन्य मर्केन्टाइल एजेंट जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो अपने व्यापार मे सॉलप्तता के परिणामस्वरूप या उसके संबंध मे या प्रासंगिक या उसके दौरान किसी मालिक या मालिकों जो घोषित या अघोषित हो सकते हैं की ओर से सामान खरीदता है या बेचता है या आपूर्ति या वितरण करता है।

- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

11. बी ओ टी अनुबंध को ध्यानपूर्वक जांच करने से पता चलता है कि ऐसे अनुबंधों में डीवैट अधिनियम 2004 की धारा 2(जेड सी) तथा (जेड ओ) में पिरभाषित कार्य संविदा के स्वरूप के विनिमय होते हैं इसलिए डीवैट अधिनियम 2004 के अंतर्गत कार्य स्विदा की पिरभाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं । इस प्रकार श्री के के दिहया, अतिरिक्त आयुक्त (विशेष क्षेत्र) द्वारा दिए गए आवेदन में यथावर्णित बिक्री एवं खरीद के विनिमय की प्रकृति तथा डीवैट अधिनियम 2004 के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते आवेदक की डीवैट अधिनियम 2004 की धारा 85 के अंतर्गत आवेदन में उठाए गए प्रश्नों पर निम्नलिखित व्यवस्था दी जाती है:-

- (क) बी ओ टी संविदाएं डीवैट 2004 की धारा 2(जेड सी) तथा (जेड ओ) में यथापरिभाषित कार्य संविदा की प्रकृति की है।
- (ख) इसलिए बी ओ टी संविदाएं का डीवैट एक्ट 2004 के अंतर्गत पंजीकर अनिवार्य है।
- (ग) इसी प्रकार, ऐसी संविदाओं जैसे बी ओ टी, बी ओ टी, बी ओ एम टी तथा अन्य ऐसे स्वरूप की ऐसी संबंधित संविदाओं का डीवैट एक्ट 2004 की धारा 18 के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण किया जाना है।

12 व्यवस्था पूर्वकाल से 01/04/2005 (डीवैट एक्ट 2004 के प्रारंभ से) लागू होगी।

जलज श्रीवास्तव, आयुक्त (टी एण्ड टी)

IN THE COURT OF COMMISSIONER

# DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES NOTIFICATION

Delhi, the 25th November, 2010

Subject: Levy of Tax on BOT Contract involving transation in the nature of Works Contract and Registration requirements thereof.

No: 281/CDVAT/2010/42- Sh. K. K. Dahiya, Additional Commissioner (Special Zone), Department of Trade & Taxes has filed an application U/S 85 of the DVAT Act, 2004 seeking clarification/ruling U/S 85 of the DVAT Act, 2004 on the following two points;

- (a) Whether BOT Contract are transaction in the nature of Works Contract as define in section 2 (zc) & (zo) of DVAT Act, 2004?
- (b) If the answer to question is affirmative, whether the BOT Contractors are liable for compulsory registration U/S 18 of the DV ATAct, 2004?

The said application has been filed for the purpose of notifying the exact legal position in respect of taxability and registration in BOT contracts in the nature Works Contract, both to the authorities subordinate to Commissioner (VAT), Govt of NCT of Delhi and the entities/dealers who are carrying on or who may undertake such transactions.

2. While explaining the nature of transaction of BOT contracts and its technical aspects, the applicant in the application dated 27-10-2010 has stated that in Delhi, there are number of BOT Contracts (Build, operate, transfer) in operation. Whether the Contracts are, in connection with DMRC, AIRPOTS, ROADS or POWER etc.- all such contracts incorporate material in the execution of such projects in Delhi, and liable to VAT.

3. Conceptually the BOT Contractor first builds a BOT property as per the requirement of owner/organization at site decided by the owner/organization.

The revenue streams in such contracts is toll charges that a BOT Contractor receives from the future users of the BOT property as per terms and condition given in the Contract signed by a BOT contractor and the owner/organization.

- 4. It is an admitted fact that all BOT Contracts are partially or fully transferred on back-to-back basis to a number of sub contractors for a consideration.
- 5. From the analysis of the claim of transactions in BOT cases in detail, it is to say that BOT Contractors import/locally purchase materials and give the same to various Contractors on free of charges (FOC) basis for use or the sub- contractors purchases the material, and transfer the Goods in the project. These transactions have huge revenue implications under Delhi VAT Act and Central Sales Tax Act.
- 6. In one of the cases in Special Zone, a BOT Contractor was showing purchases and claiming input tax credit / TDS certificates benefits but was not showing the taxable turnover in the returns. From the perusal or returns, it was noticed that the dealer is showing carry-forwards in each month. There is every likelihood that similarly, other dealers might be escaping tax liability on the ground that they are not liable to pay the tax, as they did not receive any payment from the contractees.
- 7. The question raised in the above said application in respect of which ruling has been sought is, whether BOT contracts are a transaction in the nature of Works contract or not, and if yes, whether the BOT contractors are liable for compulsory registration. In this connection, it is relevant to refer to the definition of term "Sale" as it figures in clause (ze) of sub-section (1) of section (2) of the DVAT Act, 2004 which read as under:

"Sale" with its grammatical variations and cognate expression means any transfer of property in goods by one person to another for cash or for deferred payment or for other valuable consideration (not including a grant or subvention payment made by one government agency or department, whether of the central government or of any state government, to another) and includes-

| (ii)   | (i)              |   |   |
|--|------------------|---|---|
| (iv)   | (ii)             | 46 .                                      |   |
| (V) Transfer of property in goods (whether as goods or some other form) involved in the execution of wor contract;  (vi) | (iii)            | ••••                                      |   |
| some other form) involved in the execution of wor contract;  (vi)  | (iv)             |   |   |
| (vii)"   | some other form) | perty in goods (whe<br>involved in the ex | ther as goods or in<br>ecution of works |
|  | (vi)             |   |   |
| (viii)"  | (vii)            | *************                             |   |
|  | (viii)           |   |   |

- 8. It is also relevant to refer to the term, "works contract" as contained in clause(zo) of sub-section (1) of Section 2 which lays down that "works contract" includes any agreement for carrying out for cash or for deferred payment or for valuable consideration, the building construction, manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, repair or commissioning of any movable or immovable property;
- 9. Equally relevant is to refer to the definition of term "Goods" as contained in the clause (m) of sub-section (1) of Section (2) which read as under:

"Goods" means every kind of movable property (other than newspaper, actionable claims, stocks, shares and securities) and includes-

- Livestock, all materials, commodities, grass or things attached to or forming part of the earth which are agreed to be served before sale or under a contract of sale; and
- (ii) Property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract, lease or hire-purchases or those to be used in the fitting out, improvements or repair of movable property;
- 10. It is also relevant to refer to the term "dealer" as contained in clause (j) of sub-section (1) of Section (2) which lays down that:

"dealer" means any person who, for the purposes of or consequential to his engagement in or in connection with or incidental to or in the course of his business, buys or sells goods in Delhi directly or otherwise, whether for cash or for deferred payments or for commission, remuncration or other valuable consideration and includes,

(i) a factor, commission agent, broker, del credere agent or any other mercantile agent by whatever name called, who for the purposes of or consequential to his engagement in or in connection with or incidental to or in the course of the business, buys or sells or supplies or distributes any goods on behalf of any principal or principals whether disclosed or not

| (n)   | •   |
|-------|-----|
| (iii) | ,,, |
| (iv)  | ,,, |
| (v)   | ,,, |
| (vi)  |     |

200

11. A careful examination of the BOT contracts reveals that such Contracts involve transactions in the nature of Works Contract as defined in Section 2 (zc) & (zo) of DVAT Act, 2004 and therefore are covered under the definition of "work contract" under DVAT Act, 2004.

10/09/11-2

So the nature of transactions of sale and purchase as explained in the application filed by Sh. K. K. Dahiya, Additional Commissioner (Special Zone) and keeping in view the provisions of DVATAct, 2004 referred to above, the ruling on the questions raised by the applicant in his application u/s 85 of the DVAT Act, 2004 is given as follows:

- a) The BOT contracts are in the nature of works contract as defined in Section 2(zc) and (zo) of the DVAT Act, 2004.
- b) The BOT contractors are, therefore, liable for compulsory registration u/s 18 of the DVAT Act, 2004.
- c) Similarly, all contracts relating with related formats of such contracts as BOO, BOOT, BOMT and other similar contracts, shall be liable for compulsory registration under Section 18 of the aforesaid DVAT Act, 2004.
- 12. This ruling shall come into force with retrospective effect i.e. w.e.f. 01-04-2005 (since the inception of DVATAct, 2004).

JALAJ SHRIVASTAVA,

Commissioner (T&T)

Addl. Commissioner (Special Zone)

T&T Department, Vyapar Bhawan,

# कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

### आदेश

दिल्ली, 11 जनवरी, 2011

सं. फा. 10 ( 1563 )/मु, स.( मुख्या. )/स.शू./7721.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स. ड्रीमलैण्ड रीयलकान प्रा. लि., सी-10, सी ब्लॉक मार्केंट, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 सं 10000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

# OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

### ORDER

Delhi the, 11th January, 2011

No. F. 10(1563)/COS(HQ)/Cons. Duty/7721.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dreamland Realcon Pvt. Ltd., C-10, C-Block Market, Vasant Vihar, New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 00001 to 10000 to be issued by the said company.

### दिल्ली, 12 जनवरी, 2011

सं फा. 10 (1574)/मु. स.(भुख्या.)/स.शु./7731.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स बुऐना विस्टा रीसोर्ट्स प्रा. लि., यूजी-37, सोमदत्त चैम्बर-1 भीकाजी कामा प्लेस, नई झिल्ली-110066 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,67,70,750 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5052651 से 6729725 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 16,771 (रुपए सोलह हजार सात सौ एकहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

### Delhi the, 12th January, 2011

No. F. 10(1574)/COS(HQ)/Cons. Duty/7731.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Buena Vista Resorts Private Limited, UG-37, Somdatt Chamber-1, Bhikaji Kama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 16,771 (Rs. Sixteen Thousand Seven Hundred Seventy One) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,67,70,750 for equity share certificates with distinctive Nos. 5052651 to 6729725 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1562)/मु. स.( मुख्या.)/स.शु./7732.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ब्लू बेल प्रोपटेक प्रा. लि., सी-10, सी ब्लॉक मार्केट, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 10000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100 (रुपए सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी!

No. F. 10(1562)/COS(HQ)/Cons. Duty/7732.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Blue Bell Proptech Pvt. Ltd, C-10, C-Block Market, Vasant Vihar, New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 00001 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1572)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./7733.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (!) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स एफसीएमएल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., ए-217, ओखला इण्ड्स्ट्रीयल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली 110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 19,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0500001 से 0690000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1900 (रुपए एक हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1572)/COS(HQ)/Cons. Duty/7733.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. FCML Projects Pvt. Ltd., A-217, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1900 (Rs. One Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 19,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 0500001 to 0690000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1576)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./7734.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स इन्टीग्रेटेड केसटेक कन्सलटेंट्स ग्रा. लि., ई-13/29, तीसरी मॉजल, हर्षा भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 20,60,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 216000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2060 (रुपए दो हजार साठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10(1576)/COS(HQ)/Cons. Duty/7734.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Integrated Casetech Consultants Private Limited, E-13/29, 3rd Floor, Harsha Bhawan, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2060 (Rs. Two Thousand Sixty) only on the aggregate value of shares of Rs. 20,60,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10001 to 216000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1566)/मु, स.(मुख्या.)/स.शु./7735.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नेशनल स्कील डवलपमेंट कॉरपोरेशन, डी-4, क्लोरियन कलेक्शन, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 51,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 7080001 से 7590000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 5100 (रुपए पांच हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1566)/COS(HQ)/Cons. Duty/7735.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling RevenueAuthority, Delhi hereby directs that M/s. National Skill Development Corporation, D-4, Clarion Collection, Shaheed Ject Singh Marg, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5100 (Rs. Five thousand one hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 51,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 7080001 to 7590000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1583)/मु. स.(मुख्या.)/स.सु./7736,—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अकांक्षा सेलुलर लि., 317, कम्पीटेंट हाउस, एफ-14, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 18,32,00,500 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3750301 से 22070350 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,83,201(रुपए एक लाख तिरासी हजार दो सौ एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1583)/COS(HQ)/Cons. Duty/7736.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Akansha Cellular Limited, 317, Competent House, F-14, Connaught Place, New Dlehi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,83,201 (Rs. One Lac Eighty Three thousand two hundred one) only on the aggregate value of shares of Rs. 18,32,00,500 for equity share certificates with distinctive Nos. 3750301 to 22070350 to be issued by the said company.

### शुद्धीपत्र

नई दिल्ली 12 जनवरी, 2011

सं फा. 10 ( 1501 )/मृ. स.( मुख्या. )/स.श./7737.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी ने आदेश सं. फा. 10 (1501)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./6259 दिनांक 24-11-2010 के द्वारा सर्वश्री सैमसंग सी एण्ड टी इण्डिया प्रा. लि., सी-2, दूसरी मंजिल, मिरा कॉरपोरेट स्युट्स, प्लॉट 1 और 2, पुराना ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065 को निर्देश दिया था कि वे उनके द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 4,65,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 80,00,001 से 1,10,00,000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 46,500 (रुपए छियालिस हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । उपरोक्त आदेश में जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की पृथक संख्या 80,00,001 से 1,11,00,000 तक पढ़ी जाये

### CORRIGENDUM

New Delhi, 12th January

No. F. 10(1501)/COS(HQ)/Cons. Duty/7737.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, directed to M/s. Samsung C & T India Pvt. Ltd., C-2, 2nd Floor, Mira Corporate Suites, Plot 1 & 2, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110065 to deposit a consolidated stamp duty of Rs.46,500 only on the aggregate value of equity shares of Rs. 4,65,00,000 bearing distinctive No. 80,00,001 to 1,10,00,000 vide order No. 10(1501)/COS(HQ)/Cons. Duty/6259 dated 24-11-2010. The distinctive No. in the above said order may be read as 80,00,001 to 1,11,00,000.

### आदेश

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2011

सं, फा, 10 (1281)/मु, स्त(मुख्या.)/स.शु./7738.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इफ्को टोकियो जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि., इफ्को सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्क सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपये 15,00,000 (रूपये पन्द्रह लाख) जो कि उनके द्वारा 01 जनवरी, 2011 से 31 मार्च, 2011 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा । कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

#### **ORDER**

Delhi the 12th January, 2011

No. F. 10(1281)/COS(HQ)/Cons. Duty/7738,—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFFCO -TOKIO General Insurance Co. Ltd., IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket, New Dlehi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 15,00,000 (Rs. Fifteen Lac) only in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the company during the period 1-1-2011 to 31-3-2011 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and counter signed by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

सं फा. 10 (1568)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./7739.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्रिस्टल प्रोपकोन प्रा. लि., सी-10, सी-ब्लॉक मार्केट, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 10,000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1568)/COS(HQ)/Cons. Duty/7739.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Crystal Propcon Pvt. Ltd., C-10, C-Block Market, Vasant Vihar, New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 00001 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1564)/मु, स.(मुख्या.)/स.शू./7740.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ऐचीवर इन्फ्राटेक प्रा. लि., सी-10, सी-ब्लॉक मार्केट, वसन्त विहार, नई दिल्ली 110057 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 10,000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100(रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1564)/COS(HQ)/Cons. Duty/7740.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Achiever Infratech Pvt. Ltd., C-10, C-Block Market, Vasant Vihar, New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 00001 to 10,000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (1565)/मु, स.(मुख्या,)/स.शु./7741, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित धारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ऐसे इन्फ्रामार्ट प्रा. लि., सी-10, सी-ब्लॉक मार्केट, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 10,000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100(रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1565)/COS(HQ)/Cons. Duty/7741,—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Arrow Inframart Pvt. Ltd., C-10, C-Block Market, Vasant Vihar, New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 00001 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1575)/मु. स.(मुख्या.)/स.शू./7742.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि., 781, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 517693 से 532692 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 15,000(रुपए पन्द्रह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1575)/COS(HQ)/Cons. Duty/7742.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Central Electronics Limited, 781, Desh Bandhu Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-I10005 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 15,000 (Rs. Fifteen Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,50,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 517693 to 532692 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (1580)/मु स.(मुख्या.)/स.शु./7743.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शार्प कैपिटल सर्विसज लि., प्लॉट नं.–9, एलएससी, गुजरावाला टाऊन-I, दिल्ली-110009 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 12,70,001 से 14,70,000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2000(रुपए दो हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1580)/COS(HQ)/Cons. Duty/7743.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-/6/2G///-3

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sharp Capital Services Limited, Plot No. 9, LSC, Gujrawalan Town-I, Delhi-110009 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2000 (Rs. Two Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 20,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 12,70,001 to 14,70,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1573)/मु. सं.(मुख्या.)/स.शु./7744.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ईपावर सोल्यूशनस इण्डिया प्रा. लि., सी-160, जेवीटीएस गार्डन्स, छत्तरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110074 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 5,00,000 मृत्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 50,000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 500(रुपए पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उकत कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1573)/COS(HQ)/Cons. Duty/7744.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Epower Solutions India Private Limited, C-160, JVTS Gardens, Chhatarpur Extension, New Delhi-110074 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500 (Rs. Five hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. I to 50,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1577)/मु. स.(मुख्या.)/स.शू./7745.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनाक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ऐस्टी एडवाइजर्स प्रा. लि., जे-6ए, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,32,05,780 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4990001 से 5178654 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 13,206(रुपए तेरह हजार दो सौ छ:) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1577)/COS(HQ)/Cons. Duty/7745.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Estee Advisor Private Limited, J-6A, Kailash Colony, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 13,206 (Rs. Thirteen thousand two hundred six) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,32,05,780 for equity share certificates with distinctive Nos. 4990001 to 5178654 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 ( 1567 )/मु. स.( मुख्या. )/स.शू./7746. -गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एकौड इन्फ्रामार्ट प्रा. लि., सी-10, सी-ब्लॉक मार्केट, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 10,000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100(रुपए एक सौ)

केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से, आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक(पंजीकरण)

No. F. 10(1567)/COS(HQ)/Cons. Duty/7746.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Accord Inframart Pvt. Ltd., C-10, C-Block Market, Vasant Vihar, New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 00001 to 10,000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi, R. K. MISHRA, Special Inspector General (Registration)